



















*प्रेम मृत्यु से अधिक शक्तिशाली है। मृत्यु जीवन से अधिक शक्तिशाली है।*

*यह जानते हुए भी मानव-मानव के मध्य कितनी संकुचित सीमा खिंची है!*

– *खलील जिब्रान*

## कल्पमेधा

# सफाई कर्मियों की सुरक्षा का सवाल

**आज भी कई जगहों पर नाले या सेंटिक टैंक की सफाई बिना सुरक्षा के श्रमिकों से कराई जाती है। हर साल बड़ी संख्या में ऐसे श्रमिकों की मौत हो जाती है, मगर पीड़ित परिवारों को न्याय कम ही मिल पाता है।**



की सफाई को पूरी तरह यांत्रिक किया जाए और सभी पीड़ित परिवारों को तत्काल उचित आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

अदालत के इस आदेश का पालन कितनी गंभीरता से हो रहा है इसका अंदाजा आए दिन सफाई के दौरान श्रमिकों की मौत से जुड़ी घटनाओं से

**दरअसल, नाले, सीवर और सेंटिक टैंक की सफाई करते वक़्त श्रमिकों की मौत के जो आंकड़े सरकारें जारी करती हैं, ये वे मामले होते हैं, जो पुलिस प्राथमिकी के जरिए सरकार तक पहुंचते हैं। इसलिए वास्तविक आंकड़ों का सही पता नहीं चल पाता है। जाहिर है कि श्रमिकों की सफाई कार्य के दौरान मौत के आंकड़े वास्तविकता से बहुत कम दर्ज हो पाते हैं। इससे साफ है कि इस तरह के हादसों में जान गंवांने वाले कई श्रमिकों के परिवारों को आर्थिक मदद भी नहीं मिल पाती है। ऐसे में अगर कमाई करने वाले इकलौते व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। मगर इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिससे दूसरों को सबक मिल सके।**

लगाया जा सकता है। यानी नाले, सीवर और सेंटिक टैंक की सफाई का कार्य आज भी मशीनी उपकरणों की जगह श्रमिकों से कराया जा रहा है,

## कला में जीवन

अलका ‘सोनी’

जीवन में विकल्पों का मौजूद होना किसी वरदान से कम नहीं होता। विकल्प हमें मनपसंद रास्ते चुनने के अभूतपूर्व सुविधा देते हैं। मगर यहाँ दुविधा तब आने लगती है, जब हम किसी विशेष विकल्प को ही महत्त्वपूर्ण मानते हुए अन्य विकल्पों को खारिज करते चले जाते हैं। आज का समय विज्ञान एवं तकनीक का है। इसलिए अक्सर पढ़ाई हो, रोजगार हो या फिर कोई और अवसर, हम विज्ञान और तकनीक को ही वरीयता देते हैं, लेकिन इस क्रम में कला पक्ष बिल्कुल पीछे छूटता चला जाता है। तो क्या कला की कोई उपादेयता नहीं होती? मनुष्य जब एक केवल जीव के रूप में जन्म लेता है, तब संस्कृति, संवेदना और सुजनशीलता ही उसे मनुष्य बनाती है। इन्हीं में कला का स्थान सर्वोच्च है। कला वह शक्ति है, जो पथ्यर में देवत्व, शब्दों में संवेदना, रंगों में भाव, सुरों में आत्मा और जीवन में सौंदर्य भर देती है। जिस समाज में कला जीवित रहती है, वहां मानवता भी जीवित रहती है।

प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो ने कहा था, ‘कला आत्मा पर जमी हुई जीवन की धूल को प्रतिदिन साफ करती है।’ वास्तव में, कला केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि आत्मा का परिष्कार है। यह मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाती है और उसे जीवन के गहरे अर्थों से परिचित कराती है। आज का युग कुत्रिम बुद्धिमत्ता, तकनीकी विकास और तीव्र प्रतिस्पर्धा का युग है। इससे मनुष्य के पास सुविधाएं तो बढ़ी हैं, पर मानसिक शांति कम हुई है। तनाव, अकेलापन, अवसाद और असहिष्णुता जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे समय में कला मनुष्य के लिए आशा की किरण बनकर सामने आती है। संगीत मन को शांति देता है, साहित्य विचारों को दिशा देता है, चित्रकला भावनाओं को अभिव्यक्ति देती है और नृत्य शरीर तथा मन के बीच सामंजस्य स्थापित करता है।

अनेक अध्ययनों में ऐसे तथ्य उजागर हुए हैं कि कला-आधारित गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य सुधारने, तनाव कम करने तथा सामाजिक जुड़ाव बढ़ाने में प्रभावी भूमिका निभाती हैं। इसी प्रकार यूनेस्को का मानना है कि कला और संस्कृति शांति, सामाजिक समरसता तथा सतत विकास की आधारशिला हैं। दरअसल, कला केवल व्यक्तिगत रुचि नहीं, बल्कि सामाजिक आवश्यकता भी है। भारतीय संस्कृति में कला को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम माना गया है। मंदिरों के भित्तिचित्र एवं मूर्तियां हमारी आध्यात्मिक चेतना का परिचय देती हैं। ‘सत्यम् शिवम् सुंदरम्’ का भारतीय दर्शन बताता है कि सत्य, कल्याण और सौंदर्य- तीनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

कला का सबसे बड़ा नैतिक पक्ष यह है कि वह मनुष्य को

संवेदनशील बनाती है। जो व्यक्ति कविता पढ़ता है, संगीत सुनता है या चित्रों में भावों को पहचानता है, उसके भीतर करुणा, सहानुभूति और प्रेम का विकास होता है। हिंसा, घृणा और कट्टरता का स्थान सहिष्णुता और मानवता ले लेती है। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के संदेश को केवल भाषणों से नहीं, बल्कि भजनों, लोकगीतों और सांस्कृतिक प्रतीकों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है कि ‘कल्पना ज्ञान से अधिक महत्त्वपूर्ण है।’ दरअसल, कल्पना ही नए आविष्कारों को जन्म देती है और कल्पना का सबसे बड़ा विद्यालय कला है। एक चित्रकार रंगों से सोचता है, एक कवि शब्दों से और एक वैज्ञानिक सूत्रों से, लेकिन तीनों का आधार सृजनात्मक कल्पना ही है।

भारत की कला-परंपरा विश्व में अद्वितीय है। भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी, कथकली, मधुबनी, वारली, पट्टंचित्र, लोकगीत, लोकनाट्य, शास्त्रीय संगीत और लोकवाद्य हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। इन्हें संरक्षित रखना केवल परंपरा का सम्मान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का माध्यम भी है। आज कला रोजगार और आत्मनिर्भरता का भी सशक्त आधार बन चुकी है। केवल परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर लेना ही सफलता नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य संवेदनशील, जिम्मेदार और नैतिक नागरिक तैयार करना भी है। अगर विद्यालयों में संगीत, नाटक, चित्रकला और साहित्य को समान महत्त्व दिया जाए, तो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और समस्या-समाधान की योग्यता अपने आप विकसित होगी।

वास्तव में, कलाकार समाज का दर्पण भी होता है और उसका पथप्रदर्शक भी। इतिहास में अनेक सामाजिक आंदोलनों को साहित्य, रंगमंच और लोककलाओं ने नई दिशा दी है। कला अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का सबसे प्रभावी और शांतिपूर्ण माध्यम भी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम कला को केवल शौक न समझें, बल्कि जीवन का अनिवार्य अंग बनाएं। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कला से जुड़कर अपने व्यक्तित्व को अक्षम संतुलित और समृद्ध बना सकता है, फिर चाहे वह लेखन हो,

संगीत हो, चित्रकला हो, नृत्य हो या हरतशिल्प।

कला मनुष्य के अंदर छिपी शक्ति को पहचानने और अभिव्यक्त करने का श्रेष्ठ माध्यम है। यह हमें सिखाती है कि जीवन केवल उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि संवेदनाओं, सौंदर्य, करुणा और सृजन का उत्सव भी है। यह मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, संस्कृति को संरक्षित रखती है और समाज को अधिक मानवीय बनाती है। जब हम कला को जीवन की आवश्यकता के रूप में स्वीकार कर लेंगे, इसे लेकर सहज हो जाएंगे, तब हमारा समाज अधिक संवेदनशील, अधिक रचनात्मक और अधिक शांतिपूर्ण बन सकेगा। विज्ञान हमें जीवन जीने के साधन देता है, पर कला हमें जीवन जीने का कारण देती है।

# संपादकीय

जनसत्ता | 14 जुलाई, 2026

## कसौटी पर पात्रता

कोई भी सरकारी योजना शुरू करने से पहले लाभार्थियों को केंद्र में रखकर उसके लिए नियम-शर्तें तय की जाती हैं। इसी आधार पर पात्र लोगों का चयन कर संबंधित योजना का लाभ उन तक पहुंचाया जाता है। मगर किसी योजना को चुनाव से ठीक पहले लागू किया जाए और उसी सरकार के फिर से राज्य में कमान संभालने के बाद अगर बड़ी संख्या में लोगों को पात्रता की सूची से बाहर कर दिया जाए, तो उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। खबरों के मुताबिक, राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ से नब्बे लाख से ज्यादा महिलाओं को बाहर कर दिया है। यानी इन महिलाओं को पहले इस योजना का लाभ दिया जा रहा था, लेकिन अब वे या तो पात्रता के मानदंडों को पूरा नहीं कर पाई हैं या फिर ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा न कर पाने की वजह से उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या इस योजना में नई नियमावली जोड़ी गई है! अगर ऐसा नहीं है, तो फिर क्या वजह है कि जो महिलाएं पहले पात्र थीं, अब वे अपात्र हो गई हैं?

गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनावों से कुछ समय पहले जून, 2024 में इस योजना को मंजूरी दी थी। इसके तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाएं प्रति माह डेढ़ हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इस योजना में राज्य की 2.4 करोड़ महिलाओं को शामिल किया गया था। मगर अब फिर से सत्तासीन हुई महायुति सरकार ने ई-केवाईसी प्रक्रिया के तहत लाखों महिलाओं के नाम इस योजना से बाहर कर दिए हैं। सवाल है कि शुरू में इन महिलाओं को किस आधार पर पात्र घोषित किया गया था? क्या तब दस्तावेजों की जांच सही ढंग से नहीं की गई थी या फिर इसके पीछे इससे चुनावी लाभ उठाने की मंशा थी? हालांकि सरकार का दावा है कि पचास से पचपन लाख महिलाएं तय समय सीमा में ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाईं। मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कम शिक्षित और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाएं ई-केवाईसी की बारीकियों को नहीं समझ पाती हैं। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि इस कार्य में उनकी सहायता के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए जाएं।

राज्य सरकार के मुताबिक, लगभग बारह लाख महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय इस योजना की निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई। जबकि पैतालीस लाख से अधिक महिलाएं पैंसठ वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को पार कर चुकी थीं। हैरत की बात तो यह है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब चौदह हजार पुरुष भी महिला बनकर इस योजना का लाभ ले रहे थे, जिन्हें अब बाहर कर दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकारी योजनाओं में पात्रता मानदंडों की जांच में किस कदर लापरवाही बरती जाती है। यही नहीं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में भी राज्य सरकार की इस योजना के क्रियान्वयन में वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने इस योजना के लिए स्वीकृत कुल बजट के मुकाबले साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए। साथ ही जमा खातों में हजारों करोड़ रुपए रखने और वित्तीय प्रबंधन में कमियों को भी उजागर किया गया है। ऐसे में अब यह मांग की जा रही है कि इस योजना की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए, ताकि सच सामने आ सके।

## दावों के बरक्स

उत्तर प्रदेश में सरकार का दावा रहा है कि उसने अपराध और अपराधियों के खिलाफ जिस स्तर पर सख्ती और कार्रवाई की है, उसकी वजह से राज्य की जनता खुद को सुरक्षित महसूस करती है। खासतौर पर महिलाओं के लिए एक सुरक्षित माहौल बना है और कहीं भी आने-जाने में उन्हें किसी तरह के असुरक्षा-भाव से नहीं गुजरना पड़ता। सरकार के इस तरह के दावे निश्चित रूप से आम जनता की सुरक्षा के लिहाज से अहम हैं, लेकिन सवाल है कि क्या राज्य में सरकार और पुलिस का प्रभाव वास्तव में इतना असरकारी है कि किसी भी वारदात को अंजाम देने से पहले अपराधी कानून से खौफ खाते हैं! गौरतलब है कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में निर्माणाधीन व्यावसायिक परिसर में सাত वर्षीय बच्ची का शव मिला, जिसकी हालत देख कर उससे बलात्कार के बाद उसकी हत्या की आशंका भी जताई गई है। खबर के मुताबिक, वहीं मजदूरी कर रहे परिवार की उस बच्ची को बहला-फुसला कर ले जाया गया और इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया। इस घटना के अलावा भी हाल के दिनों में नाबालिग बच्चियों से बलात्कार या उनकी हत्या के अन्य मामले सामने आए और न्याय की मांग के साथ लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा।

यह छिपा नहीं है कि आए दिन राज्य सरकार अपना प्रभाव साबित करने के उद्देश्य से अपराध को खत्म कर देने की दुहाई देती रहती है। यह भी दावा किया जाता रहता है कि कानून के डर से अब अपराधी राज्य छोड़ कर भाग चुके हैं। अगर सरकार के दावे सही हैं, तो ऐसा क्यों है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के भीतर कानून का कोई खौफ नहीं दिखता और वे महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराधों को अंजाम देने से भी नहीं हिचक रहे? यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कई बार आपराधिक घटनाओं की संख्या थानों में दर्ज आंकड़ों के मुकाबले वास्तव में कहीं ज्यादा होती हैं। कहने को महिलाओं के लिए राज्य को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से कानून से लेकर हर स्तर पर चौकसी बरतने और हेल्पलाइन की व्यवस्था करने जैसे उपाय किए गए हैं। मगर सच्चाई यह है कि सरकारी दावों के समांतर अभी भी ऐसा तंत्र सक्रिय करने की जरूरत है, जो महिलाओं के लिए वास्तव में सुरक्षित माहौल बना सके।

जिससे हर साल बड़ी संख्या में जहरीली गैसों या आक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो जाती है। चिंता की बात यह है कि न तो केंद्र सरकार की ओर से बनाए गए कानून का पूरी तरह से पालन हो पा रहा है और न ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का। ऐसे में इस तरह से होने वाली श्रमिकों की मौत को कैसे रोका जाए, यह एक बड़ा सवाल है।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में श्रमिकों की सुरक्षा और उनके कार्य की परिस्थितियों को लेकर एक कानून बनाया था। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता नामक इस कानून में काम के दौरान श्रमिकों की सुरक्षा, खतरनाक गैसों से बचाव और उन मशीनी उपकरणों का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है, जिनके जरिए आसानी से नालों और सेंटिक टैंकों की सफाई की जा सकती है। सवाल यह है कि कानून में सख्त प्रावधान होने के बावजूद सीवर की सफाई में आज भी मशीनी उपकरणों के इस्तेमाल के बजाय इस कार्य को बिना सुरक्षा के श्रमिकों से ही क्यों कराया जा रहा है? कानून का उल्लंघन किस तरह हो रहा है, इसका ताजा उदाहरण पिछले माह दिल्ली के मुंडका में सीवर की सफाई के दौरान जहरीली गैस से तीन श्रमिकों की मौत हो जाने की घटना है। इसे भी सामान्य घटना मानकर अनदेखा कर दिया गया।

दरअसल, सीवर, नाले और सेंटिक टैंक की सफाई का कार्य अक्सर ठेकेदारों के जरिए कराया जाता है। वे मशीनी उपकरणों की जगह श्रमिकों से यह कार्य करावते हैं, ताकि उन्हें ज्यादा पैसा खर्च न करना पड़े। वे नियम-कानून की भी कोई परवाह नहीं करते हैं। इस जोखिम भरे कार्य में जब किसी सफाईकर्म की मौत हो जाती है, तो ज्यादातर मामलों में ठेकेदार अपनी जिम्मेदारी से बच निकलते हैं। अगर किसी ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होती भी है, तो नाममात्र के लिए। ऐसे मामलों में दर्ज प्राथमिकी में इतनी कमजोर धाराएं लगाई जाती हैं कि दोषी मामूली दंड पाकर छूट जाता है और पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता भी नहीं मिल पाती है।

विईबना यह है कि ऐसे श्रमिकों की सफाई कार्य के दौरान मौत के आंकड़े भी वास्तविकता से बहुत कम दर्ज हो पाते हैं। दरअसल, नाले, सीवर और सेंटिक टैंक की सफाई करने वाले श्रमिकों की मौत के जो आंकड़े सरकारें जारी करती हैं, ये वे मामले होते हैं, जो पुलिस प्राथमिकी के जरिए सरकार तक पहुंचते हैं। इसलिए वास्तविक आंकड़ों का सही पता नहीं चल पाता है। सफाई मजदूर संगठनों की मानें तो सरकारी आंकड़े की अपेक्षा वास्तविक आंकड़े में कई गुना का अंतर है। इससे साफ है कि इस तरह के हादसों में जान गंवांने वाले कई श्रमिकों के परिवारों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद भी नहीं मिल पाती है।

ऐसे में अगर कमाई करने वाले इकलौते व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। मगर इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिससे दूसरे लोगों को सबक मिल सके। सवाल है कि मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग या फिर मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने वाले संगठन क्या कभी भी ऐसे श्रमिकों की मौत को लेकर मुखर होंगे? जब बात अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की आती है, तो समाज के हर वर्ग के उत्थान का दावा करने वाले राजनीतिक दलों की संवेदनाएं आखिर कहां गुम हो जाती हैं!

**दांव पर रोजगार**

विकसित भारत गारंटी फार रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण ने मनरेगा का स्थान ले लिया है। इसके तहत गारंटीकृत कार्य की अवधि सी दिनों से बढ़ा कर 125 दिन कर दी गई है। हालांकि, आलोचकों का तर्क है यह पुराने वाले से बेहतर नहीं है। यह योजना कानूनी अधिकार से हट कर एक बजट-सीमित लाभ में तब्दील हो गई है, जिससे राज्यों को लागत का 40 फीसद तक भुगतान करना पड़ता है। जबकि पहले राज्यों को केवल चार से पांच फीसद राशि का भुगतान करना पड़ता था। जो काम कुछ सौ करोड़ में हो जाता था, अब राज्यों को इसके लिए दस हजार से लेकर 20 हजार करोड़ तक की राशि देनी पड़ेगी। यह कहां से आएगा? केंद्र सरकार ने अपने सिर का बोझ कम कर राज्यों के कंधों पर करीब आधी जिम्मेदारी डाल दी है। पुराने कानून द्वारा गारंटीकृत काम मिलता था। यदि स्थानीय श्रमिकों को रोजगार चाहिए होता था, तो सरकार को उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना पड़ता था। नई योजना एक तय बजट पर काम करती है। यह सार्वभौमिक गारंटी को हटा देता है, जिससे काम सीमाओं के अधीन हो जाता है।

– *जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर*

**गुम होता बचपन**

आज शिक्षा का उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, लेकिन नर्सरी और प्राथमिक कक्षाओं में ही पढ़ाई का इतना अधिक बोझ डाल दिया जाता है कि उनका बचपन कहीं खो जाता है। भारी बस्ता, लंबा-चौड़ा पाठ्यक्रम, रोज का ‘होमवर्क’ और जटिल ‘स्कूल प्रोजेक्ट’ बच्चों से अधिक उनके माता-पिता के लिए परीक्षा बन जाते हैं। बच्चों की रचनात्मकता विकसित नहीं हो पाती। ज्ञान के बजाय भारी-भरकम फीस वसूलना स्कूलों का उद्देश्य रह

**मतदाताओं की मुश्किल**

दिल्ली में मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए घर-घर फार्म वितरित किए जा रहे हैं। मगर बड़ी संख्या में लोगों को फार्म भरने में कठिनाई हो रही है। कई लोग फार्म अधूरा या गलत भर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सभी राजनीतिक दलों और स्वयंसेवी संस्थाओं को अपने-अपने क्षेत्रों में निशुल्क सहायता केंद्र स्थापित करने चाहिए, जहां प्रशिक्षित स्वयंसेवक फार्म सही तरीके से भरवाएं, आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दें और लोगों की शंकाओं का समाधान करें। इन

**भ्रष्टाचार की परतें**

पिछले दिनों लखनऊ में एक पूर्व अधिकारी के घर छापेमारी में कई किलो सोना-चांदी और 35 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति मिलना भ्रष्टाचार के अलावा उस प्रशासनिक कमजोरी का संकेत भी है, जिसके कारण ऐसी गतिविधियां वहीं तक बिना रोक-टोक चलती रहती हैं। इतनी संपत्ति एक दिन में अर्जित नहीं हुई होगी। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है कि समय रहते इस सबकी जांच क्यों नहीं हुई? यदि निगरानी व्यवस्था नियमित और प्रभावी होती, तो संपत्तः अनियमितताओं का पहले ही पता लगाया जा सकता था। अगर नियमों की अनदेखी कर अपात्र लोगों को लाइसेंस या वाहनों को अनुचित फिटनेस प्रमाणपत्र दिए गए होंगे, तो इसका असर सड़क सुरक्षा और आम नागरिकों के जीवन पर भी पड़ा होगा। इसलिए भ्रष्टाचार केवल अवैध धन अर्जित करने का नहीं, बल्कि उतराधिक्य से जुड़ा गंभीर विषय है।

– *हिमांशु सिंह लखनऊ*



## नृत्य

बंगलुरु : कोवि के इलामक्कारा में स्कूली बच्चों के बीच कथकली प्रस्तुत करता एक कलाकार ।

## बोल

यूक्रेन अपनी राजनीतिक रणनीति में बदलाव कर रहा है। विदेश नीति की जिम्मेदारी ऐसे अनुभवी व्यक्ति को सौंपी जाएगी, जो निर्णयों को प्रभावी ढंग से लागू कर सके और यूक्रेन की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। - लोदोमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति



## बोल

नेपाल व भारत कूटनीतिक पहल के जरिये सीमा विवाद सुलझा सकते हैं। सीमा से जुड़े मुद्दों को ऐतिहासिक तथ्यों, दस्तावेजों और मानचित्रों के आधार पर कूटनीतिक पहल और बातचीत से सुलझाया जा सकता है। - शिशिर खनाल, नेपाल के विदेश मंत्री



## सम-सामयिक

## हाइड्रोजन ट्रेन: कम दूरी की यात्रा में नई तस्वीर गढ़ने की तैयारी

## जनसत्ता संवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन-चालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यह हरित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय रेलवे के लिए अहम उपलब्धि होगी। इस क्षेत्र में अब तक कुछ ही देशों ने कदम रखा है।

फ्रांसीसी रेलिंग स्टॉक कंपनी एल्सटॉम ने 2016 में बर्लिन में एक प्रदर्शनी में इस तकनीक



## फायदे

भारत में जो ट्रेन चलाई जाएगी, वह दुनिया के सबसे लंबे (आठ यात्री डिब्बे और दो ड्राइविंग पावर डिब्बे) और सबसे शक्तिशाली (2400 किलोवाट) हाइड्रोजन ट्रेनसेट में से एक है। यह ट्रेन 89 किलोमीटर लंबे जौंद-सोनीपत रेलवे खंड पर कम से कम 682 यात्रियों को 75 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति से ले जा सकती है।

हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन और आक्सीजन

के संयोजन से विद्युत उत्पन्न करने के सूत्र पर चलती हैं। भारतीय हाइड्रोजन ट्रेन के मामले में- दोनों ड्राइविंग पावर कार में हाइड्रोजन ईंधन सेल और लिथियम फेरो फास्फेट बैटरी से युक्त एकीकृत पावर पैक के चार सेट होंगे। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जहाज पर उच्च दबाव पर संग्रहित हाइड्रोजन (440 किलोग्राम) और बाहर की हवा से आक्सीजन को ग्रहण करेगा, फिर उन्हें मिलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करेगा।

एक पावर पैक 300 किलोवाट ऊर्जा उत्पन्न करेगा- जिसमें से 115 किलोवाट ईंधन सेल से और 185 किलोवाट लिथियम फेरोफास्फेट बैटरी से प्राप्त होगी। चारों पावर पैक मिलकर कुल 1200 किलोवाट बिजली प्रदान करेंगे।

ट्रेन में कुल उत्पादित बिजली 2400 किलोवाट (3200 हार्सपावर) हो जाती है।

हाइड्रोजन सेल और बैटरी के पावर पैक की कार्यप्रणाली के बारे में अधिकारी ने बताया, 'फ्यूल सेल सतत विद्युत उत्पादन करता है, जिसका अर्थ है कि यह ट्रेन की बदलती विद्युत मांग के साथ घटना-बढ़ता नहीं है। जब ट्रेन चलना शुरू करती है, तो वह शुरू में फ्यूल सेल से बिजली लेती है, और चूंकि उस समय ट्रेन को बिजली की आवश्यकता कम होती है, इसलिए फ्यूल सेल से अतिरिक्त बिजली ट्रेन की बैटरी को चार्ज करने में उपयोग होती है। जैसे-जैसे ट्रेन की गति बढ़ती है और उसकी बिजली की मांग बढ़ती है, फ्यूल सेल के अलावा, बैटरी भी बिजली देने लगती है।'

उन्होंने बताया, 'बाद में, जब ट्रेन को बिजली की आवश्यकता कम हो जाती है, खासकर जब ट्रेन स्टेशन के पास पहुंच रही होती है, तो बैटरी की बिजली बंद हो जाती है और फ्यूल सेल की अतिरिक्त ऊर्जा बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देती है। इस प्रकार, एक पूरा चक्कर लगाने के बाद, यात्रा के अंत में बैटरी लगभग 80 फीसद चार्ज हो जाती है। इस प्रणाली का मुख्य भाग - ईंधन सेल - कनाडा की कंपनी बैलार्ड से आयात किया गया है, जो इसके उत्पादन में विशेषज्ञता

रखती है। सामान्य वायुमंडलीय दबाव को एक 'बार' के रूप में मापा जाता है। हालांकि, हाइड्रोजन को 200-500 बार के दबाव पर संग्रहित करना पड़ता है। ट्रेनों में स्वच्छ ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग करने में यही सबसे बड़ी चुनौती है। हाइड्रोजन का उत्पादन स्तर कम है और इसका परिवहन कठिन है।

ट्रेनों के लिए हाइड्रोजन की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, रेलवे ने जींद में 3000 किलोग्राम क्षमता वाली ईंधन भरने की सुविधा स्थापित की है। हाइड्रोजन को वितरण के दौरान -15 डिग्री सेल्सियस पर रखने के लिए एक चिलर प्लांट भी विकसित किया गया है। कम तापमान इसे तरल अवस्था में बदल देगा और इस प्रकार, इसके आसान वितरण को सुनिश्चित करेगा।



## शोध

## अंटार्कटिका की बर्फीली धरती में मिला नैनोप्लास्टिक

## जनसत्ता संवाद

प्लास्टिक प्रदूषण अब केवल शहरों, नदियों और समुद्रों तक सीमित नहीं रह गया है। दुनिया के सबसे दूर और साफ माने जाने वाले इलाकों में भी इसके कण पहुंच रहे हैं। वैज्ञानिकों ने पहली बार अंटार्कटिका की मिट्टी में नैनोप्लास्टिक पाए हैं। यह खोज वैज्ञानिक पत्रिका 'साइंटिफिक रिपोर्ट्स' में प्रकाशित हुई है।

प्लास्टिक के बेहद छोटे कण होते हैं नैनोप्लास्टिक, जिनका आकार एक माइक्रोमीटर से भी कम होता है। ये आसानी से हवा, पानी और मिट्टी के माध्यम से फैल सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कण पर्यावरण और जीवों के लिए माइक्रोप्लास्टिक से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये कोशिकाओं के अंदर तक पहुंच सकते हैं और जहरीले प्रदूषकों को अपने साथ ले जा सकते हैं।

अंटार्कटिका को लंबे समय से धरती का सबसे साफ और सुरक्षित क्षेत्र माना जाता रहा है। यहां कोई स्थायी आबादी नहीं रहती और औद्योगिक गतिविधियां भी बहुत कम हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में वैज्ञानिकों ने वहां के समुद्री पानी, बर्फ, तटों और समुद्री जीवों में प्लास्टिक के निशान पाए हैं।

शोधकर्ताओं ने जनवरी 2023 में अंटार्कटिका की 'मैकमर्डो ड्राई वैली' के टेलर और राइट वैली क्षेत्रों से मिट्टी के नमूने लिए। उन्होंने ऊपरी सतह की 13 जगहों से और 20 सेंटीमीटर से अधिक गहराई वाली चार जगहों से मिट्टी एकत्र की। इन नमूनों की जांच के लिए वैज्ञानिकों ने एक नई और अत्यधिक संवेदनशील तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे 'थर्मल डीसाप्शन-प्रोटान ट्रांसफर रिएक्शन-मास स्पेक्ट्रोमेट्री' कहा



## विश्व परिक्रमा

## अमेरिका : मतदान प्रक्रिया बदलने की कोशिश में ट्रंप

## जनसत्ता संवाद

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहां मतदान प्रक्रिया में बदलाव की कोशिश की है। उन्होंने एक संघीय निर्वाचन आयोग के उन सदस्यों को हटा दिया है, जिन्होंने वोट देने के इच्छुक लोगों के लिए पंजीकरण से पहले अपनी अमेरिकी नागरिकता के दस्तावेज दिखाने को अनिवार्य बनाने की कोशिशों का विरोध किया था। वाइट हाउस ने 'निर्वाचन सहायता आयोग' के सदस्यों के खिलाफ शासकीय कार्रवाई की पुष्टि की।

यह आयोग राज्यों को संघीय अनुदान देता है, मतदान प्रणाली की जांच की निगरानी करता है और राष्ट्रीय मतदाता पंजीकरण फार्म का रखरखाव करता है। यह



कदम रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक रखने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस कोशिश का हिस्सा है, जिसके जरिए



## जानें-समझें

## भारत, इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड

## हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भरोसे की कूटनीति

## जनसत्ता संवाद

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत 'भरोसे की कूटनीति' पर काम कर रहा है। तीन देशों - इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का मकसद हिंद-प्रशांत में भारत के भरोसेमंद साझेदारों के साथ रिश्ते मजबूत करना रहा। इस विशाल समुद्री क्षेत्र की रणनीतिक तस्वीर तेजी से बदल रही है। कोशिश यह है कि इस क्षेत्र के देश अपने फैसले खुद लें और बाहरी महाशक्तियों पर कम निर्भर रहें।

## समावेशी विकास व सहयोग

आने वाले वर्षों में हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर भारत की खास रणनीतिक सोच है। नए दृष्टिकोण का उद्देश्य केवल महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है, बल्कि समावेशी विकास, साझा समृद्धि और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत हिंद-प्रशांत में सहयोग का एक नया माडल चाहता है, जो अमेरिका या चीन की नीतियों पर आधारित न होकर, इस क्षेत्र के देशों की जरूरतों और हितों के अनुसार तैयार हो। भारत का मानना है कि इस क्षेत्र के भविष्य का फैसला वही देश करें, जो यहां रहते हैं और जिन पर इसके सबसे अधिक प्रभाव पड़ते हैं।

## अहम है हिंद-प्रशांत

हिंद-प्रशांत की किसी भी रणनीति में इंडोनेशिया महत्वपूर्ण कड़ी है। यह देश प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव था। यह देश हिंद-प्रशांत क्षेत्र के सबसे प्रमुख शक्तियों में से एक है। यह द्वीपीय देश हिंद और प्रशांत महासागर के बीच मौजूद लगभग सभी महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित है। इसके पास प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर संपदा है। भारत और इंडोनेशिया के बीच सालाना व्यापार लगभग 30 अरब डालर के करीब है। यह भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाले व्यापार से भी अधिक है और भारत-जर्मनी व्यापार के लगभग बराबर है। भारत और इंडोनेशिया के पास इस क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की क्षमता, संसाधन और रणनीतिक मौजूदगी है। दोनों देश मिलकर हिंद-प्रशांत में सुरक्षा प्रदान करने वाली प्रमुख शक्तियां बन सकते हैं। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से भारत और इंडोनेशिया की ही है।



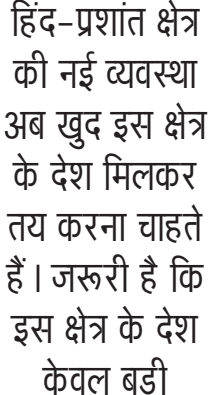
(फाइल फोटो)



साझेदारी पर जोर है। पश्चिम की ओर यह साझेदारी संयुक्त अरब अमीरात, खाड़ी के देशों और अफ्रीका के पूर्वी तट तक फैली है।

- वीना शिकरी, पूर्व राजनयिक

भारत की कोशिश है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी एकजुट रहे। पूर्व में इंडोनेशिया, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ



शक्तियों द्वारा बनाए नियमों को मानने तक सीमित न रहें, बल्कि वे खुद इस क्षेत्र के नियम, प्राथमिकताएं और भविष्य तय करें।

- शशांक, पूर्व विदेश सचिव

## भारत और आस्ट्रेलिया

आस्ट्रेलिया आज भारत का तेजी से उभरता हुआ महत्वपूर्ण साझेदार बन गया है। साल 2022 में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता हुआ। दोनों देश वित्तीय सेवाओं, परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधनों के प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की कवायद में जुटे हैं। इन क्षेत्रों में भारत और आस्ट्रेलिया दोनों की मजबूत क्षमताएं हैं, और दोनों का लक्ष्य तकनीकी आत्मनिर्भरता, बड़े स्तर पर उत्पादन और नई तकनीकों का विकास करना है। जब यह सहयोग और मजबूत हो जाएगा, तो अगला लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में संयुक्त शक्तियां बन सकते हैं। इससे भारत और आस्ट्रेलिया पूरे हिंद-प्रशांत और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकेंगे।

## न्यूजीलैंड से रणनीतिक साझेदारी

न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी का अहम हिस्सा है। वह उन्नत विनिर्माण (एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग), अंतरिक्ष तकनीक, डीप टेक और कृषि प्रसंस्करण (एग्री-प्रोसेसिंग) जैसे क्षेत्रों में काफी आगे है। भारत के नवाचार, खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने की रणनीति में न्यूजीलैंड अहम है। न्यूजीलैंड के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र है। इसलिए समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत और आओटेआरोआ (न्यूजीलैंड का माओरी नाम) के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। आस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड भी भारत के लिए 'फाइव आइज' सुरक्षा और खुफिया सहयोग नेटवर्क तक पहुंच में महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है।

- प्रस्तुति : दीपक रस्तोगी



## व्यक्तित्व

## अर्नव : विंबलडन क्वार्टर फाइनल में 36 साल बाद भारत की दस्तक

## जनसत्ता संवाद

आइटीएफ जूनियर विश्व नंबर 19 अर्नव पापरकर विंबलडन जूनियर बायज सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले 36 साल में पहले भारतीय बन गए। आठ जुलाई को उन्होंने जापान के रयो ताबाता को 6-2, 6-1 से हराया। 18 वर्षीय पापरकर ने भारतीय टेनिस इतिहास में कुछ खास खिलाड़ियों का नाम दर्ज कराया है। देश के अखिरी खिलाड़ी जो इस मुकाम तक पहुंचे थे, वे 1990 में लिपंडर पेस थे। इससे पहले, पापरकर ने जूनियर विश्व नंबर 3, अमेरिका के कीटन हैंस को 6-2, 6-3 से हराकर सबको चौंका दिया था। छह फीट से कुछ अधिक लंबे पापरकर ने इस साल की शुरुआत में



इंडियन टेनिस डेली को बताया था कि वह अपनी पहली सर्व को अपना मुख्य हथियार मानते हैं। हैंस के खिलाफ उनकी यही खूबी काम आई, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए छह ऐसे लगाए, अपने सामने आए सभी ब्रेक प्वाइंट्स बचाए और अपनी सर्व पर केवल 18 अंक गंवाए।

हेमंत वेद्रे टेनिस अकादमी में कोच प्रसेनजीत पाल के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे पापरकर ने हैंस के पहले दौर के प्रदर्शन का अध्ययन किया और मौका मिलते ही खेल में उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्हें महाराष्ट्र राज्य लान टेनिस एसोसिएशन (एमएसएलटीए) और

महाटेनिस फाउंडेशन ने वित्तीय मदद दी है।

साथ ही, 'मिशन लक्ष्यवेध' से सरकारी सहायता भी मिली है। पापरकर ने बताया, 'जहां मैं तैरने जाता था, उसके ठीक बगल में एक टेनिस कोर्ट था। मैं वहां टेनिस देखता था। जब मैं छह साल का था, तो कोच ने मुझे टेनिस में शामिल होने के लिए कहा और मैंने खेलना शुरू कर दिया।' अर्नव के माता-पिता ने उनके अंतरराष्ट्रीय

टूर्नामेंट यात्रा का खर्च वहन किया और उन्हें वैश्विक मानकों के लिए तैयार करने के लिए स्पेन में प्रशिक्षण के लिए भेजा। अर्नव को पहली बड़ी सफलता 2023 में मेलबर्न में आयोजित प्रतिष्ठित आस्ट्रेलियाई ओपन अंडर-14 एशिया-पैसिफिक एलीट ट्राफी में मिली। उसी वर्ष बाद में, उन्होंने वाइल्डकार्ड क्वालीफायर के रूप में प्रवेश करते हुए कोल्हापुर में राष्ट्रीय अंडर-16

चैंपियन का खिताब जीता। उन्होंने 2024 में अपने 16वें जन्मदिन पर एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट में पदार्पण किया, क्योंकि उन्हें वाइल्डकार्ड के रूप में प्रवेश दिया गया था। उन्होंने अपने पहले प्रमुख अंतरराष्ट्रीय जूनियर खिताब जीते, जिनमें बहरीन में आयोजित आइटीएफ जे60 मनामा और 2025 में आयोजित जे200 कुआलालंपुर शामिल हैं। जनवरी में उन्हें एआईटीए बायज अंडर-18 नेशनल नंबर एक खिलाड़ी का खिताब मिला और उन्होंने लगातार 21 हफ्तों तक शीर्ष स्थान बनाए रखा। उन्होंने रोलैंड गैरो जूनियर चैंपियनशिप 2026 के तीसरे दौर में पहुंचकर वैश्विक शीर्ष 20 में जगह बनाई।



नया ट्रेंड • भारतीय गेमर अब कैजुअल, फ्री गेम्स छोड़कर शूटर, स्ट्रैटजी जैसे प्रतिस्पर्धी गेम्स की तरफ बढ़ रहे, इससे इन-एप खरीदारी बढ़ रही, सालाना 14.5% बढ़ रहा बाजार

देश में 60 करोड़ गेमर, 2025 में 795 करोड़ मोबाइल गेम डाउनलोड, एशिया में सबसे ज्यादा

भारकर न्यूज़ | मुंबई

मोबाइल गेमिंग मार्केट करवट ले रहा है। 'मिक्सी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स' की रिपोर्ट के मुताबिक, गेमर अब कैजुअल, फ्री गेम्स छोड़कर शूटर, स्ट्रैटजी जैसे प्रतिस्पर्धी गेम्स खेल रहे हैं। इससे इन-एप खरीदारी तेजी से बढ़ रही है। रियल मनी गेमिंग यानी सट्टा आधारित गेम्स पर सख्ती के बाद गेमर का रुख गैर-सट्टा गेमिंग की तरफ मुड़ गया है। नॉन-आरएमजी गेमिंग बाजार 2025 में ₹10,527 करोड़ का रहा, जो इस साल ₹14,350 करोड़ और 2029 तक 23,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। देश में 60 करोड़ सक्रिय गेमर हैं।

मुफ्त गेम पसंद, पर पिछले 5 साल में इन-एप खरीदारी से कमाई दोगुनी से भी ज्यादा ₹7,656 करोड़ हुई

सबसे तेज़ ग्रोथ: 2025 में देश में 795 करोड़ मोबाइल गेम डाउनलोड हुए, जो पूरे एशिया में सबसे ज्यादा है। गेमर भी सालभर में 9% बढ़कर 60 करोड़ हो गए।

फ्री गेम्स पसंद: भारतीय गेमर ज्यादातर मुफ्त गेम्स पसंद करते हैं। विज्ञापन कमाई का बड़ा जरिया है। 2025 में इन-गेम विज्ञापन से कंपनियों को ₹2,871 करोड़ की कमाई हुई।

तेज़ ग्रोथ: हर साल ढाई गुना तक बढ़ रही गेमिंग से कमाई

गेम कैटेगरी

आय वृद्धि

एमओबीए 234%

कार्ड बैटलर 92%

4X स्ट्रैटजी 77%

स्रोत: मिक्सी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स

देश का पूरा गेमिंग मार्केट इस साल ₹48,000 करोड़ तक

2026

₹48,000

करोड़ का बाजार (RMG मिलाकर)

2031

₹94,000

करोड़ से ऊपर जाने का अनुमान

सालाना बढ़ोतरी

14.52%

गेमिंग स्टार्टअप 2,364

बड़ी कंपनियां

गरेना/फ्री फायर, कृष्णा गेम्स/बीजीएमआई-क्राफ्टन, नज़ारा टेक्नोलॉजीज, ड्रीमा1, गेम्सक्राफ्ट

इक्विटी • मिडिल ईस्ट में तनाव, फिर भी ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म भारत को लेकर ‘बुलिश’

इकोनॉमी सुधर रही, सेंसेक्स एक साल में 10% चढ़ सकता है: गोल्डमैन सैक्स

विदेशी निवेशकों की हो रही वापसी, ये बड़ा संकेत

भारकर न्यूज़ | मुंबई

भारतीय शेयर बाजार तेजी का नया दौर देख सकता है। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक, अगले 12 महीनों में सेंसेक्स-निफ्टी में करीब 10% तेजी देखी जा सकती है। बैंकिंग और लार्जकैप शेयर जिसकी अगुवाई करेंगी। बावजूद इसके कि मिडिल ईस्ट तनाव फिलहाल बाजार पर दबाव बनाए हुए है।

गोल्डमैन सैक्स ने निफ्टी-50 के लिए जून 2027 का लक्ष्य 26,500 तय किया है। सोमवार को भारतीय बाजार पश्चिम एशिया में बढ़े भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में करीब 3% उछाल चलते दबाव में रहे। फिर भी सेंसेक्स 76,857 अंक के निचले स्तर से 932 अंक तक चढ़ गया। हालांकि आखिरकार सिर्फ 47 अंकों की तेजी के साथ 77,616 पर बंद हुआ। निफ्टी भी केवल 4 अंक चढ़कर 24,211 पर फ्लैट बंद हुआ। विश्लेषकों के मुताबिक, यह भारतीय बाजार धीरे-धीरे मजबूत होने का स्पष्ट संकेत है। अब कच्चे तेल में तेजी सेंसेक्स और निफ्टी गिरने की फौरी वजह होती थी।

ग्रासिम 17,200 करोड़ में सिंग्र एनर्जी को खरीदेगी

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

आदित्य बिड़ला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने रिन्युएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए शेल-समर्थित सिंग्र एनर्जी को खरीदेगी। यह अधिग्रहण ₹17,200 करोड़ में होगा। यह डील आदित्य बिड़ला रिन्युएबल्स के जरिए की जाएगी। यह देश की सबसे बड़ी ग्रीन एनर्जी डील में से एक है। इस अधिग्रहण से कंपनी का पोर्टफोलियो में 4.4 गीगावाट से बढ़कर 9.3 गीगावाट हो जाएगा, जो कंपनी के 10 गीगावाट के लक्ष्य के बेहद करीब है। सिंग्र एनर्जी के पोर्टफोलियो में 3.3 मौजूदा गीगवाट क्षमता और 1.7 गीगावाट निर्माणाधीन क्षमता शामिल है। कंपनी इस अधिग्रहण के लिए कर्ज लेगी और अपनी पूंजी का भी इस्तेमाल करेगी। यह डील 31 दिसंबर, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। समूह आगामी वर्षों में 20 गीगावाट से अधिक क्षमता निर्माण का लक्ष्य लेकर चल रहा है।

बिजनेस एंकर

एआई का पोस्टर, रॉकेट का बिजनेस... निवेशकों को देर से समझ आई स्पेसएक्स की असली कहानी, बाजार में लिस्ट होने के पहले ही महीने शेयर पीक से 35% गिरे

भारकर न्यूज़ | मुंबई

12 जून की वो शाम याद कीजिए, जब एलन मस्क की स्पेसएक्स पहली बार शेयर बाजार में उतरी थी। कंपनी ने शेयर का दाम 135 डॉलर तय किया था। लेकिन बाजार खुलते ही भाव 150 डॉलर तक पहुंच गया। दिन भर में यह 176 डॉलर तक चढ़ा और आखिर में 160.95 डॉलर पर बंद हुआ। यह इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन चुका था। अगले हफ्ते तो हद ही हो गई- शेयर 225 डॉलर तक पहुंच गया। इसके साथ ही स्पेसएक्स मार्केट कैप के मामले में अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट को भी पीछे छोड़ चुकी थी।

बिना कैश चुकाए खरीदी ₹5.7 लाख करोड़ की कोडिंग कंपनी

16 जून को जब स्पेसएक्स का शेयर उछाल पर था, ठीक उसी दिन कंपनी ने कोड लिखने वाले एआई बॉट स्टार्टअप कर्स को 60 अरब डॉलर (₹5.7 लाख करोड़) में स्पेसएक्स के शेयर चुकाकर खरीद लिया। चूँकि उस वक़्त स्पेसएक्स के शेयर की कीमत आसमान पर थी, मस्क ने असल में बिना नक़द खर्च किए ही यह कंपनी हासिल कर ली। विश्लेषक सैमुअल कर इसे बाजार की ऐसी समझ बताते हैं जो शायद ही किसी अन्य कंपनी के पास हो।

बीबीसी वर्ल्ड की एक रिपोर्ट में निवेश रिसर्च कंपनी सीएफआरए के विश्लेषक कीथ स्माइडर ने कहा है, 'मस्क जिस भी कंपनी को ख़ूते हैं, लोग उत्साहित हो जाते हैं। लेकिन यह पहला मौका था जब लोगों को लगा कि वे किसी ऐसी चीज़ में निवेश कर रहे हैं जिसे एआई प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया जा रहा था।' दरअसल, इसी साल स्पेसएक्स ने मस्क की ही एआई कंपनी एक्सएआई को खरीदा था, जिसे अब स्पेसएक्स एआई नाम दिया गया है और जो चैटबॉट प्रोजेक्ट के लिए जानी जाती है। लेकिन असलियत सामने आते ही तस्वीर बदलने लगी। स्पेसएक्स की असली कमाई तो रॉकेट बनाने, उन्हें लॉन्च करने और स्टारलैंक सैटेलाइट सर्विस से होती

है। जैसे ही स्टारलैंक ने अमेरिका के मेम्फिस इलाके में डेटा सेंटर को लेकर स्थानीय विरोध के बीच कीमतें घटाने का ऐलान किया, उस दिन शेयर 8% तक गिर गया। 3 जुलाई को जब स्पेसएक्स को नैस्टेक-100 इंडेक्स में शामिल किया गया, तब भी पूरा इंडेक्स 1.7% गिरा, लेकिन स्पेसएक्स का शेयर 4.4% टूटा।

बिजनेस

Business Standard

और

TheEconomist

की खबरों के साथ

शूटर कैटेगरी से कमाई में 94% हिस्सेदारी 2 कंपनियों की

- डाउनलोड में सिमुलेशन, आर्केड गेम्स आगे, आय में शूटर गेम्स अक्वल।
- फ्री फायर मैक्स और बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया मिलकर भारतीी गेम मार्केट में शूटर कैटेगरी की कुल कमाई में 94% हिस्सेदारी रखते हैं।
- हाई-एंड शूटर एक्सपीरियंस की मांग बढ़त रही है। यानी गेमर अब सिर्फ हल्के-फुल्के गेम्स नहीं, बल्कि ज्यादा ग्राफिक्स और गहराई वाले शूटर गेम्स भी पसंद कर रहे हैं।
- स्माइपर गेम्स भारत में सबसे तेजी से बढ़ती कैटेगरी बनकर उभरे हैं।

अब स्थानीय भाषा, थीम वाले गेम का बोलबाला बढ़ रहा

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय गेमिंग अब भी कम कमाई वाला बाजार बना हुआ है। लेकिन बेहतर लोकलाइजेशन, भारत-केंद्रित टून्मेंट और बदलते उपभोक्ता व्यवहार से आगामी वर्षों में खर्च बढ़ने की उम्मीद है। लूडो किंग और क्रिकेट लीग जैसे स्थानीय गेम्स सांस्कृतिक जुड़ाव के दम पर कई ग्लोबल गेम्स को डाउनलोड में पीछे छोड़ रहे हैं। जो बताता है कि आगे स्थानीय भाषा और थीम वाले गेम्स भारतीय बाजार में बड़ी भूमिका निभाएंगे।

सस्ते का भ्रम • 4 स्मार्टफोन कंपनियों के 12 मॉडलों की ऑनलाइन ‘प्राइस स्टडी’ रिपोर्ट

फोन पर ‘सेल’ डिस्काउंट छलावा, बचत नहीं हो रही

हर्ष शिवम | नई दिल्ली

ऑनलाइन सेल में दिखने वाले भारी डिस्काउंट अमूमन वास्तविक बचत नहीं कराते। टेकआर्क के विश्लेषण के मुताबिक, अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्मस सेल से पहले कीमतें बढ़ाईं, फिर सेल में सिर्फ उतनी ही घटा दी। इसके चलते ग्राहक अक्सर लॉन्च प्राइस से भी ज्यादा दाम चुका रहे होते हैं।

वनप्लस, सैमसंग, नथिंग और लावा के 12 मॉडलों की तुलना से पता चला कि ज्यादातर डिवाइस ‘लॉन्च प्राइस’ से महंगे ही बिके, भले ही ‘सेल प्राइस’ पहले के लिस्ट प्राइस से कम दिखें। टेकआर्क की स्टडी में शामिल 50 स्मार्टफोन में से 34 यानी

| 10 में से 7 स्मार्टफोन ‘सेल’ में लॉन्च प्राइस से भी महंगे |              |            |             |
|-----------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------|
| मॉडल                                                      | लॉन्च प्राइस | सेल प्राइस | असली फर्क   |
| वनप्लस 15                                                 | 72,999       | 81,999     | 12.3% महंगा |
| फोन 4ए प्रो                                               | 39,999       | 41,999     | 5% महंगा    |
| गैलेक्सी एफ70ई                                            | 12,499       | 12,999     | 4% महंगा    |
| फोन 4ए                                                    | 31,999       | 32,999     | 3% महंगा    |
| अगिन 4                                                    | 24,999       | 24,249     | 3% सस्ता    |
| वनप्लस 15R                                                | 47,999       | 48,999     | 2.1% महंगा  |
| गैलेक्सी एफ36                                             | 17,499       | 17,999     | 2.9% महंगा  |
| बोल्ड एन1 5जी                                             | 12,999       | 13,249     | 2% महंगा    |
| गैलेक्सी एस25 अल्ट्रा                                     | 1,29,999     | 84,999     | 34.6% सस्ता |
| गैलेक्सी एस25                                             | 80,999       | 56,999     | 29.6% सस्ता |

68% मॉडल जून तक लॉन्च प्राइस से ऊपर बिक रहे थे- सेल शुरू होने से पहले ही। इसकी वजह मेमोरी चिप की बढ़ती लागत है, जिसका बोझ

कंपनियों ने 2026 की पहली छमाही में कीमतों में बढ़ोतरी करके ग्राहकों पर डाला। डिस्काउंट में भी इससे राहत नहीं मिली।

मौका • 2030 तक 2.5 लाख करोड़ का होगा बाजार, अभी से ढाई गुना

30 करोड़ घरों में लग सकता है रूफटॉप सोलर; अभी सिर्फ 40 लाख में, 3 कंपनियों का दबदबा

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

देश के 30 करोड़ योग्य घरों में से अभी सिर्फ 40 लाख पर सोलर लगे हैं, यानी इसकी पहुंच महज 1.3% है। सरकारी सहायता और पीएम सूर्य घर योजना से दिसंबर 2026 तक इसे 75 लाख घरों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस तेजी से इस सेक्टर का बाजार 2030 तक 2.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने का अनुमान है। इस सेक्टर में अभी सिर्फ तीन कंपनियाँ- टाटा पावर, वारी एनर्जीज और सर्वोटेक का दबदबा है।

तेजी: सोलर अपनाने की रफ्तार 18% से अधिक... सोलर अपनाने की सालाना रफ्तार 18% से अधिक है। स्विसडी मिलने से मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए सोलर पैनल लगाना बेहद किफायती हो गया है। मौजूदा प्रोजेक्ट्स के चलते अगले कुछ महीनों में उपकरणों की रिकॉर्ड मांग रहेगी। यह क्षेत्र अब सरकारी योजनाओं से निकलकर रिटेल बाजार में बड़ी क्रांति लाने को तैयार है।

टाटा पावर का 19.5% मार्केट शेयर... टाटा पावर 11 साल से देश की सबसे बड़ी रूफटॉप प्रोवाइडर है। वित्त वर्ष 2026 में इसका रेवेन्यू दोगुना होकर 4,759 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का शुद्ध मुनाफा 150% उछलकर 499 करोड़ रुपए पहुंच गया है। देश के कुल सोलर इंस्टॉलेशन में हर 6 में से 1 यानी 16.7% वारी एनर्जीज का है। वित्त वर्ष 2026 में इसका रिटेल बिजनेस 84% बढ़कर 5,515 करोड़ रुपए रहा। कंपनी अपनी मांड्र्यूल क्षमता 28 गीगावाट तक बढ़ा रही है।

डेरिंटनी • टैक्स न चुका पाने के चलते अपना पसंदीदा कॉटेज

तक नहीं बचा पाए दुनिया के मशहूर ‘टैक्स मास्टर’ डिवक्सन

लंदन | अन्रस्ट एंड यंग के पूर्व टैक्स चीफ जॉन डिवक्सन (70) की सालाना कमाई कभी ₹25.60 करोड़ थी। अब वह ₹7.7 करोड़ टैक्स न चुका पाने के चलते अपना खुबसूरत थैच्ड रूफ कॉटेज ‘टोड हॉल’ खोने वाले हैं। डिवक्सन ने 2010 में पत्नी जेनेट के नाम सब कुछ ट्रांसफर कर दिया था। 2017 में वे दिवालिया घोषित कर दिए गए। कोर्ट ने उनके ट्रस्ट को फ्रांड मानते हुए रद्द कर दिया। अब ट्रस्टीज उनका घर बेचने की तैयारी में हैं। डिवक्सन ने अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया। पूर्व डाइनिंग स्ट्रीट विजिटर अब स्टेट पेंशन पर गुजर-बसर कर रहे हैं।

यूपीआई से डिजिटल गोल्ड में निवेश ढाई गुना

ग्रॉसरी, सुपरमार्केट में UPI पेमेंट 31%, कुल 23% बढ़े

अजितव्य कवाले | मुंबई

देश में बढ़ते डिजिटल पेमेंट के बीच ग्रॉसरी और सुपरमार्केट में यूपीआई का इस्तेमाल सबसे ज्यादा बढ़ा है। एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक, जून में इस श्रेणी में ट्रांजेक्शन की संख्या 31.3% बढ़ गई। इस दौरान कुल 373.95 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए, जबकि जून 2025 में यह संख्या 284.81 करोड़ थी। बीते महीने कुल यूपीआई पेमेंट 23.5% बढ़े। अब लोग किराने के सामान के लिए कैश के बजाय डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं। यूपीआई के जरिए डिजिटल सोना खरीदने का ट्रेंड लोकप्रिय हो रहा है।

उछाल: ब्रोकर्स को सबसे ज्यादा पेमेंट, 38% बढ़ा

वैल्यू के आधार पर सिक्युरिटीज ब्रोकर्स को बिक गए यूपीआई पेमेंट में सबसे अधिक 38.5% उछाल आया। जून में ब्रोकर्स को ₹60,945 करोड़ के पेमेंट हुए। इसके उलट, डेट कलेक्शन एजेंसियों को होने वाले भुगतान में 20.4% गिरावट आई।

मसलन, जून में डिजिटल गोल्ड के 23.49 करोड़ ट्रांजेक्शन के जरिए ढाई गुना ₹2,552.52 करोड़ का निवेश हुआ। पिछले साल जून में यह आंकड़ा सिर्फ ₹948 करोड़ था।

भारकर नॉलेज

हर ऑनलाइन गेम सट्टा नहीं होता, इनमें फर्क समझें

सामान्य गेम (जैसे शूटर, स्ट्रैटजी, आर्केड) में जीत या हार खिलाड़ी के कौशल और रणनीति पर निर्भर करती है। पैसा सिर्फ गेम के अंदर हथियार, कैरेक्टर या लेवल जैसी चीजें खरीदने में खर्च होता है। 'रियल मनी' जीतने का कोई दावा नहीं होता। वहीं रियल मनी गेमिंग (आरएमजी) गेम्स में खिलाड़ी असली पैसा दांव पर लगाते हैं और नतीजे के आधार पर पैसे जीतते या हारते हैं। इस पर भारत में 2025 में सख्ती की गई है।